इंफ्रास्ट्रक्चर | परियोजनाओं पर खर्च होंगे ₹2.48 लाख करोड़

निवेश के लिए तैयार होगा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर

Anand.tripathi@timesofindia.com

लखनऊ : विधानसभा चुनाव अगले साल होने है। इसके बाद भी योगी सरकार ने बजट के जरिए लोकलुभावन योजनाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और निवेश के रंग को और गाढ़ा करने की भरपूर कोशिश की है। प्रदेश में बने औद्योगिक निवेश के माहौल को विस्तार देने और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बजट में पूंजीगत व्यय 2.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है। इसमें 1.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर होगा। इसी तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज विभाग का बजट बढ़ाकर 32,090 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2025-26 की तुलना में 67% अधिक है।

गंगा एक्सप्रेस-वे सोनभद्र तक

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार करते हुए सोनभद्र के शक्तिनगर से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे का नाम विंध्य एक्सप्रेस-वे होगा। यह मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इसके लिए ₹500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। इसके लिए भी ₹500 करोड़ का प्रावधान है। विंध्य एक्सप्रेस-वे को सोनभद्र से चंदौली होते हुए गाजीपुर तक विस्तार देकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ने की योजना है। इसके लिए भी ₹500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जन सुविधाओं के लिए ₹15 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक विकास का बजट 13% बढ़ा

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है।

MSME सेक्टर की योजनाओं के लिए ₹3,822 करोड़ की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार और नए औद्योगिक क्षेत्रों के प्रोत्साहन के लिए ₹5,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

₹34,468 करोड़ से नई सड़कें और पुल

सड़क और सेतु के निर्माण, चौड़ीकरण और मेनटनेंस के लिए ₹34,468 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए ₹400 करोड़ दिए गए हैं। पुल निर्माण के लिए ₹4,808 करोड़ और रेलवे ओवरब्रिज के लिए ₹1,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण के लिए ₹3,700 करोड़, राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए ₹3,700 करोड़ और सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहरों में बाईपास, रिंग रोड और चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए ₹1,500 करोड़, औद्योगिक पार्कों के मार्ग चौड़ीकरण-निर्माण के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इन पर भी रकम की बौछार

- **₹100** करोड़ अतिरिक्त दिए अयोध्या में विकास कार्यों के लिए
- **₹26,514** करोड़ नगर विकास के लिए
- **₹18290** करोड़ सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए
- **₹22,676** करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में वॉटर कनेक्शन के लिए
- **₹900** करोड़ एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर के लिए
- **₹260** करोड़ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए

किस विभाग को कितनी रकम

विभाग	रकम (करोड़ रुपये में)
PWD	29,369
नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति	22,464
ऊर्जा	20,955
खाद्य एवं रसद	17,876
ग्राम्य विकास	17,435
भारी एवं मध्यम उद्योग	12,327
सिंचाई	11,942
बेसिक शिक्षा	6,727
आवास	6,165
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	5,704

एयर कनेक्टिविटी भी होगी बेहतर

प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी पर राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ₹2,111 करोड़ खर्च करेगी। जेवर इंटरनैशनल एयरपोर्ट के लिए ₹750 करोड़, जबकि हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹1,100 करोड़ का इंतजाम है।

शहरों के पास बनेंगे इकॉनमिक रीज़न

शहरों में इकॉनमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में सिटी इकॉनमिक रीजन बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान है। काशी-मीरजापुर और कानपुर-झांसी इकॉनमिक रीजन विकसित किया जाएगा।

शहरों के विस्तार के लिए ₹3,500 करोड़

शहरों के विस्तार और नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए ₹3,500 करोड़, जबकि आवास एवं शहरी नियोजन के लिए ₹7,705 करोड़ की व्यवस्था की गई है। एलडीए सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए ₹800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था की गई है।